भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 943
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

कौशल विकास कार्यनीतियों की आवश्यकता

†943. श्री आदित्य यादव:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या शैक्षिक संस्थानों में कौशल विकास कार्यनीतियों की आवश्यकता है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन और सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एनईपी 2020 प्री-स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में एकीकरण और समावेशन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और मूल्यों के विशिष्ट समूह की पहचान करके शिक्षार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम रूपरेखा और क्रियान्वयन तंत्र की भी परिकल्पना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन कौशलों और मूल्यों को शिक्षण और अधिगम की आकर्षक प्रक्रिया के माध्यम से आत्मसात किया जा सके।

एनईपी 2020 स्थानीय कौशल आवश्यकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्पों के एकीकरण के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक रूपरेखा को बढ़ावा देता है, जो कक्षा छह से ही शुरू हो।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को प्रारंभिक, स्कूल, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को शामिल करते हुए एक व्यापक क्रेडिट फ्रेमवर्क, अर्जित प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता/वृत्तिक स्तर सहित व्यावसायिक कौशल और प्रायोगिक शिक्षण जैसे विभिन्न आयामों में शिक्षण के क्रेडिटकरण को समेकित करते हुए शुरू किया गया

हैं। अन्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा संयुक्त रूप से एनसीईआरएफ़ तैयार किया गया है। इसमें सभी शिक्षण और असाइनमेंट के क्रेडिट, संचयन, भंडारण, क्रेडिट के हस्तांतरण और मोचन तथा मूल्यांकन के अध्यक्षीय का प्रावधान है भेदभाव को दूर करता है और व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच अकादमिक समतुल्यता स्थापित करता है जबकि उनके भीतर और उनके बीच गतिशीलता को सक्षम करता है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों के कौशल संवर्धन के लिए, एआईसीटीई ने कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:

- एआईसीटीई ने इंटरशिप नीति के माध्यम से इंटरशिप को तकनीकी शिक्षा का एक एकीकृत हिस्सा बना दिया है। तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल इंटरशिप दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इंटरशिप एआईसीटीई द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए जारी किए गए मॉडल पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक है।
- सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, एआईसीटीई शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।
- एआईसीटीई ने एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में अप्रेंटिसशिप अन्तर्निहित डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसमें अप्रेंटिसशिप घटक वाले पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि छात्रों को उद्योग के लिए तैयार किया जा सके और संभावित रोजगार को बढ़ाया जा सके।
- छात्रों और संकाय सदस्यों की इंटरशिप, कौशल और उन्नयन की सुविधा के लिए अग्रणी उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

रोजगार क्षमता में सुधार लाने और उद्योग-अकादमिक क्षेत्र के बीच मजबूत संबंध बनाने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए प्रशिक्षुता/इंटरशिप आधारित डिग्री कार्यक्रम संचालित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यूजीसी ने दिनांक 4 सितंबर, 2020 को यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इसके बाद, दिनांक 1 जुलाई, 2021, 18 जुलाई, 2022 और 2 मई, 2024 को संशोधन अधिसूचित किए

गए हैं। यूजीसी ने 108 उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को ओडीएल कार्यक्रम और 99 एचईआई को ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता/अधिकार प्रदान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के सहयोग से 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने तथा शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी प्रस्तुति का विस्तार करेगा। यह प्लेटफॉर्म छात्रों/शिक्षार्थियों को अग्रणी उद्योग और शिक्षाविदों से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करता है, जो उन्हें पुनः कौशल और कौशल बढ़ाने और रोजगार के लिए तैयार होने में मदद कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने अग्रणी उद्योग भागीदारों के साथ 55 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 22 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर 320 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और 1.27 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल संवर्धन के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नामांकन कराया है।

भारतीय युवाओं को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण के चार क्षेत्रीय बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। एनएटीएस ने 8.72 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है और विगत पांच वर्षों में इस योजना के तहत 1298 करोड़ रुपये वजीफा अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है। कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और देश भर में प्रशिक्षण देने के लिए जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित/संलग्न किए जाते हैं।